(b) and (c) Government considered a package of assistance for Hindustan Cables Ltd. (HCL) and a strategy for its future. The details are as under:-

I. (i) Government has decided to extend Government Guarantee to HCL for raising commercial loans from Financial Institutions/Public Sector Undertakings upto Rs. 60 crores for a period of one year.

(ii) Department of Telecommunication has been asked to examine the claims filed by HCL and pay the undisputed claims immediately. DoT has so far paid an amount of Rs. 31.14 crores to HCL against its claims.

(iii) Deptt. of Telecommunication and Hindustan Cables Ltd. have been asked to bilaterally work out the ways and means to see how the operations of the company may be sustained for the time being.

DoT has placed an order for 12 LCKM of Jelly Filled Cables on HCL along with 50% advance for execution during the last quarter of current financial year.

(iv) Government has also approved in principle, for conversion into joint ventures of the units of HCL individually or the company as a whole with suitable joint venture partners on the basis of even ceding majority share holding to the joint venture partners and for appointment of Consultants/ Marchant Bankers to undertake studies to explore the possibilities and identify suitable joint venture partners who can bring in requisite capital, technology and marketing expertise.

II. HCL has submitted a proposal for capital restructuring which is under consideration.

(d) The annual expenditure on Corporation Office by HCL in Calcutta for the year 1995-96 was Rs. 3.12 crores.

(e) No proposal is under consideration to relocate the Corporate Office of HCL at

पिछड़े क्षेत्रों के लिए औद्योगिक नीति में सुधार

948. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए औद्योगिक नीति में व्यापक सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा किए जाने के बाद देश के पिछड़े राज्यों को लाभ नहीं हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार, उदारीकृत औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक विकास में उपयुक्त प्रोत्साहनों और निवेशों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के छितराव को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। तथापि, किसी विशेष क्षेत्र/जिले का औद्योगिकीकरण करने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। अधिकतर राज्य सरकारें उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन दे रही हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए कई निवेश संबंधी आशय पत्र दायर किये गये हैं।

Automatic Approval to Foreign Investment in Industry

949. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether FICCI and ASSOCHAM have expressed their reservations on the latest decision of Government for expanding the list for the automatic entry of foreign capital to more industries and raising their equity to 74 per cent;

(b) if so, the details thereof and reasons therefor; and

(c) whether Government's decision would not amount to a serious concern for the self-reliant basis of the economy for many small scale industries in the country?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) Government policy with respect to industry and investment

objective of growth including the growth of industry and investments. The decision to expand the list for automatic approval has accordingly been taken by Government to facilitate expeditious approval of proposals. Government have taken due care to ensure that the interests of the small scale sector are protected.

पिछड़े क्षेत्रों में विदेशी निवेश का उपयोग

950. श्री नागमणि: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत के पिछड़े क्षेत्रों में विदेशी निवेश का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इन क्षेत्रों का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है; इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार की नीति के अनुसार अनिवासी भारतीयों को भारत में कहीं भी निवेश करने की छूट है और इसके लिए परियोजना का स्थान निवेशक की पसंद पर निर्भर करता है।

(ग) जी, नहीं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार विकास केन्द्र योजना, समन्वित आधारभूत संरचना विकास योजना और परिवहन राज सहायता योजना चला रही है।

बिहार में उद्योगों की स्थापना

951. श्री नागमणि: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में और विशेषकर बिहार में नये उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या ये सुविधाएं उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) भारतीय उद्योगों को गतिशील तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने घरेलू तथा विदेशी निवेश दोनों ही के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कई कदम उठाये है। 14 उद्योगों की एक छोटी सूची के अलावा जिनके लिये औद्योगिक अनुमोदन अपेक्षित है, सभी अन्य उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। हाल ही में 1997 के प्रेस नोट संख्या 2 द्वारा विदेशी इक्यूटी के लिये स्वत: अनुमोदनार्थ उद्योगों की सूची का विस्तार किया गया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वत: अनुमोदनार्थ 74 प्रतिशत विदेशी इक्यूटी तक के लिये कतिपय श्रेणियों को शामिल किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने विकास केन्द्र योजना तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिये परिवहन आर्थिक सहायता योजना भी आरंभ की है। भारत सरकार की अवसंरचना क्षेत्र में तथा विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों में निवेश हेतु करावकाश की योजना भी है। जहां तक बिहार में सुविधाओं का प्रश्न है औद्योगिक विकास प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों को उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। भारत सरकार की विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत बिहार के लिये 6 विकास केन्द्र अनुमोदित किये गये है तथा आज तक उन्हें 750 लाख रु की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ख) और (ग) इन सुविधाओं की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा जब कभी भी आवश्यक होता है नीतिगत परिवर्तन किये जाते है।

Slack in industrial growth rate

952. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRI JANARDHANA POOJARY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether growth in industrial production has continued to be slack so far in the current year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government have taken/ propose to take to increase production?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) Yes, Sir. The deceleration in industrial growth has been due to constraints in infrastructure sectors, terms of credit availability, lower demand from export and other sectors etc. Sector specific strategies have been initiated to remove constraints in [illegible] for ir[illegible]ors. Corr[illegible]